भारत की समुद्री मछली उत्पादन में बड़ी छलांग

2020-21 के 34.76 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 44.95 लाख टन उत्पादन

नई दिल्ली, 21 अगस्त.भारत में समुद्री मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. 2020-21 में जहाँ उत्पादन 34.76 लाख टन था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 44.95 लाख टन हो गया. औसतन वार्षिक वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रही. यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को संसद में दी.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में आंके गए 135 समुद्री मछली संसाधनों में से 91.1 प्रतिशत सतत पाए गए. आईसीएआर के विभिन्न अनुसंधान संस्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं और जलवायु-सहिष्णु मत्स्य एवं जलीय कृषि रणनीतियाँ विकसित कर रहे हैं. राष्ट्रीय

नवाचार जलवायु-सहिष्णु कृषि कार्यक्रम के तहत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और केरल में आर्द्रभूमि मत्स्यपालन पर अध्ययन किए जा रहे हैं. समुद्री क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग, मछली पकड़ने के अनुमान, समुद्री खेती , महासागर अम्लीकरण, ब्लू कार्बन अध्ययन और अनुकूल प्रबंधन पर शोध चल रहा है. मत्स्य समुदायों को जलवायु प्रभावों के प्रति तैयार करने के लिए ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और केरल में जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जलवायु अनुकूलन और शमन में अहम भूमिका निभा रही है. योजना के तहत सतत मत्स्य पालन, पर्यावरण-अनुकूल जलीय कृषि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है. कृत्रिम रीफ और सी-रैंचिंग कार्यक्रम इसके बड़े पारिस्थितिकीय प्रयासों में शामिल हैं. पीएमएमएसवाई के तहत 100 तटीय मछुआरा गांवों को जलवायु-सहिष्णु और आर्थिक रूप से सक्षम केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है. प्रत्येक गांव पर केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इसके अलावा, योजना के अंतर्गत 58 मत्स्य बंदरगाह और लैंडिंग सेंटर 3,281.31 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही कोल्ड स्टोरेज, फिश रिटेल व थोक बाजार, मूल्य संवर्धन इकाइयाँ और कटाई के बाद परिवहन सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है.

> मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी नेटफिश पहल के माध्यम से 2007 से अब तक 45,500 से अधिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे करीब 15 लाख हितधारक जुड़े. इन उपायों से कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम हुए, समुद्री खाद्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ, मछुआरों की आय बढ़ी और भारतीय समुद्री निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हुई है.

2030 तक 1.9 ट्रिलियन डॉलर छुएगा खुदरा बाजार

नयी दिल्ली, 20 अगस्त. भारत का खुदरा क्षेत्र 2030 तक लगभग 1,930 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है. इस क्षेत्र के सालाना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. डेलॉयट-फिक्की की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह देश का मजबूत घरेलू बाजार है, जो वैश्विक व्यापार में हो रहे उतार-चढ़ाव से भारत को बचाने में मदद करता है.रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है. देश में घरेलू खरीदारी बढ़ रही है, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है, लोग महंगे और बेहतर उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं तथा शहरों के साथ-साथ छोटे और नए बाजारों में ई-कॉमर्स का विस्तार हो रहा है.

जीएसटी 2.0 बनेगा ग्रोथ इंजन

उपभोग बढ़ेगा, राजस्व सुधरेगा, महंगाई घटेगी

कर कटौती से राजस्व नुकसान की भरपाई संभव

नई दिल्ली,20 अगस्त. 5.5 लाख करोड़ रुपए की उपभोग वृद्धि से वित्त वर्ष 26 में जीएसटी राजस्व में 52,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी, जो जीएसटी 2.0 सुधारों से होने वाले 45,000 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व नुकसान की आसानी से भरपाई कर देगा. यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई.

जीएसटी 2.0 से उपभोग, कर राजस्व में वृद्धि और मुद्रास्फीति में कमी आएगी. एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी 2.0 से उपभोग में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी और विकास दर में वृद्धि होगी. रिपोर्ट में कहा गया है, औसत राजस्व हानि लगभग 85,000 करोड़ रुपए हो सकती है. वित्त वर्ष 26 के लिए यह 45,000 करोड़ रुपए हो सकती है. कुल मिलाकर राजस्व हानि को कम करने की संभावना है क्योंकि हानिकारक वस्तुओं को 28 प्रतिशत स्लैब से 40 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है.

जीएसटी 2.0 व्यवस्था से औसतन 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने के बावजूद, खपत में 1.98 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है. कर कटौती के साथ, इसका कुल प्रभाव अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय में 5.31 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि के बराबर है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत के बराबर है.

विश्लेषकों ने पहले चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीएसटी कर कटौती से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए उधारी बढ़ाई जाती है तो सरकार के राजकोषीय अनुमानों से समझौता हो सकता है.

मुद्रास्फीति में 5-10 आधार अंकों की कमी

सेवाओं के लिए जीएसटी दरों को रेशनलाइज करने से अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में 5-10 आधार अंकों की कमी आएगी, जिसका 25 प्रतिशत प्रभाव भी शामिल है . रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में 20 से 25 आधार अंकों की कमी आने की उम्मीद है .पिछले चार वर्षों में केंद्र ने औसतन अनुमानित कर राजस्व से 2 .26 लाख करोड़ रुपए अधिक प्राप्त किए हैं .

जुलाई में म्यूचुअल फंड निवेश ने बनाए रिकॉर्ड

कोलकाता, 20 अगस्त (यूएनआई). भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग ने जुलाई 2025 में निवेश प्रवाह के मामले में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं. आईसीआरए एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह उछाल संरचनात्मक, आर्थिक और निवेशकों के व्यवहार संबंधी कारणों का परिणाम है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों का भरोसा विशेषकर इक्विटी बाजार में बढ़ा है, जहाँ जोखिम लेने की क्षमता में तेजी से सुधार हुआ है. इसका असर सेक्टोरल/थीमैटिक, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल-कैप और मिड-कैप फंड्स में रिकॉर्ड निवेश के रूप में सामने आया है.

छोटे शहरों से भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, जिसका श्रेय वित्तीय साक्षरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आसान उपलब्धता को जाता है.

मैक्रोइकोनॉमिक मोर्चे पर, मजबूत बुनियादी ढांचे और 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कटौती की संभावना ने शॉर्ट-ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स में डेब्ट फंड्स के प्रवाह को बढ़ावा दिया.

वर्कडे के थर्ड-पार्टी डेटाबेस में बड़ा डेटा उल्लंघन

नई दिल्ली, 20 अगस्त (यूएनआई) एचआर और फाइनेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वर्कडे ने अपने थर्ड-पार्टी डेटाबेस से जुड़े एक बड़े डेटा उल्लंघन की पुष्टि की है. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित ब्लॉग पोस्ट में यह जानकारी दी.रिपोर्ट के अनुसार, साइबर हमलावरों ने कंपनी के थर्ड-पार्टी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया. इस दौरान हैकर्स ने संवेदनशील जानकारी, जैसे नाम, ईमेल पते और अन्य संपर्क विवरण चुरा लिए. वर्कडे ने अपने ब्लॉग में लिखा, हाल ही में हमने पाया कि वर्कडे को निशाना बनाया गया और हमलावर हमारे थर्ड-पार्टी ष्टक्ररूप्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ जानकारी तक पहुँचने में सफल रहे.

यूपीआई लेनदेन में जबरदस्त उछाल : रिपोर्ट

जनवरी से अगस्त तक एवरेज डेली वैल्यू 75,743 करोड़ से बढ़कर 90,446 करोड़

नई दिल्ली, 20 अगस्त. यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है. इसी के साथ एवरेज डेली वैल्यू इस वर्ष जनवरी के 75,743 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त में 90,446 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, जिसमें एसबीआई 5.2 अरब ट्रांजैक्शन के साथ शीर्ष प्रेषक सदस्य रहा.

यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई.एसबीआई रिसर्च के अनुसार, अकेले जुलाई में 9.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र डिजिटल पेमेंट में अग्रणी रहा, उसके बाद 5.5 प्रतिशत के साथ कर्नाटक और 5.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान रहा. रिपोर्ट में कहा गया है, कुल वैल्यू ट्रांजेक्शन में पीयर-टू-मर्चेंट (पी2एम) ट्रांजैक्शन की हिस्सेदारी जून 2020 में 13 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2025 में 29 प्रतिशत हो गई है. इसी अवधि के दौरान, मात्रा के हिसाब से हिस्सेदारी 39 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है, जो डिजिटल पेमेंट और वित्तीय समावेशन में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.यूपीआई के नेतृत्व में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कैश इन सर्कुलेशन (सीआईसी) की संख्या से कहीं ज्यादा है.

> रिपोर्ट में कहा गया है, एनपीसीआई ने सराहनीय काम किया है, लेकिन हमारा मानना है कि एनपीसीआई को कम से कम 100 प्रमुख एमसीसी का डेटा देना चाहिए .जुलाई 2025 में टॉप 15 मर्चेंट कैटेगरी अकाउंट का लेनदेन मात्रा के हिसाब से 70 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 47 प्रतिशत रहा .किराने का सामान ट्रांजैक्शन का 24 .3 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 8 .8 प्रतिशत रहा, जबकि डेट कलेक्शन एजेंसी कैटेगरी मूल्य के हिसाब से 12 .8 प्रतिशत और मात्रा के हिसाब से केवल 1 .3 प्रतिशत रही .रिपोर्ट में कहा गया है, डेट

चीन पर निर्भरता भारत के लिए खतरा : रिपोर्ट

घरेलू विनिर्माण ही असली सुरक्षा उपाय-जीटीआरआई

100 अरब डॉलर व्यापार घाटा, आत्मनिर्भरता पर जोर

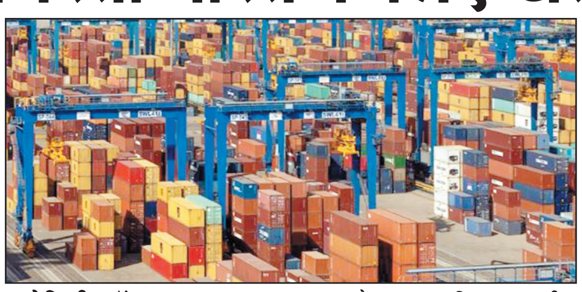

नयी दिल्ली, 20 अगस्त. भारत को दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों के निर्यात पर पाबंदियों में ढील देने का चीन का फैसला एक सकारात्मक संकेत है. हालांकि भारत को पड़ोसी देश पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम करना चाहिए जिसके साथ उसका 100 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा चिंताजनक है.

आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने बुधवार को यह बात कही.ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि 2014 से 2024 के बीच भारत के आयात परिदृश्य पर चीन का प्रभुत्व और अधिक बढ़ गया है. भारत के दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक आयात में इसकी हिस्सेदारी 57.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि मशीनरी एवं हार्डवेयर में यह 44 प्रतिशत है.

> जीटीआरआई के अनुसार, भारत के लिए एकमात्र वास्तविक सुरक्षा उपाय, निर्भरता कम करके, गहन विनिर्माण में निवेश करके और एक सच्चा उत्पाद राष्ट्र बनकर घरेलू स्तर पर मजबूती बनाना है .आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा,एक मजबूत एवं अधिक आत्मनिर्भर भारत, चीन के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में बेहतर स्थिति में होगा तथा अचानक बदलावों का शिकार होने के बजाय संबंधों को स्थिर एवं व्यावहारिक बनाए रखेगा.

केस्को को डिजिटल समाधान प्रदान करेगी टीसीएस

मुंबई, 20 अगस्त (वार्ता) टाटा समूह की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस को फिनलैंड के रिटेल समूह केस्को ने रणनीतिक साझेदार के रूप में चुना है. टीसीएस ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे नॉर्डिक्स और बाल्टिक्स इलाकों में केस्को की कोर प्रौद्योगिकी में आमूलचूल बदलाव करने की जिम्मेदारी मिली है. इस साझेदारी से केस्को को अपने परिचालन को आधुनिक बनाने, कारोबार को मजबूत बनाने और दीर्घावधि विकास को गति देने में मदद मिलेगी.

विक्रम सोलर का आईपीओ खुला

आईपीओ में 1,500 करोड़ तक के नए शेयर ,1.74 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल

मुंबई, 20 अगस्त. देश की अग्रणी सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी विक्रम सोलर लिमिटेड 19 अगस्त को अपना पहला आईपीओ लेकर आई है. कंपनी ने प्रति शेयर 315 से 332 का प्राइस बैंड तय किया है. यह इश्यू 21 अगस्त को बंद होगा. न्यूनतम 45 शेयरों की बोली लगानी होगी.

आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और प्रमोटर समूह द्वारा 1.74 करोड़ से अधिक शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है. कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्सा भी रखा गया है. जुटाई गई राशि का उपयोग सहायक कंपनी ङ्कस्रुग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाओं और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों पर होगा. 2009 में 12 मेगावाट क्षमता से शुरुआत करने वाली विक्रम सोलर अब 4.5 गीगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी मॉड्यूल निर्माता कंपनियों में शामिल है. इसके पास पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में निर्माण इकाइयाँ हैं और यह 19 राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है.

पंचायत चुनाव में क्या बदलेगी हाथी की किस्मत

लखनऊ/मेरठ. उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बड़े सवाल से जूझ रही है- क्या बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाएँगी, या उनकी राजनीतिक ताक़त का ग्राफ और नीचे खिसकेगा?

चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं मायावती भारतीय राजनीति की उन गिनी-चुनी महिला नेताओं में हैं जिन्होंने केवल सत्ता ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक समीकरण गढ़ने का हुनर भी दिखाया. लेकिन 2007 के स्वर्णिम काल के बाद बसपा का जनाधार लगातार सिमटता चला गया है.

2007 का चुनाव मायावती के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ. उस साल बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. वोट शेयर करीब 30.43 प्रतिशत तक पहुँचा. इस जीत की असली कुंजी था मायावती का रंगीन गठबंधन, जहाँ दलितों के साथ-साथ पिछड़ों और सवर्ण समुदाय को भी साधा गया. यही मॉडल उन्हें सत्ता तक ले गया और राजनीति के राष्ट्रीय नक्शे पर मायावती को सबसे मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित कर गया, लेकिन यह ऊँचाई ज्यादा दिन टिकी नहीं.

दलित वोट बैंक अब किसके पास?- बसपा की ताकत हमेशा से दलित वोटरों, खासकर जाटव समुदाय, पर टिकी रही. लेकिन पिछले तीन चुनावों में तस्वीर बदल गई. भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ गैर-जाटव दलितों को साध लिया. सपा ने पिछड़ों और मुसलमानों के साथ गठजोड़ कर दलित वोटों में भी सेंध लगाई. चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने भी युवा दलित मतदाताओं को खींचने में सफलता पाई.

मायावती की मौजूदा चुनौती

2022 के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का भी है . पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, पर लगातार घटते वोट प्रतिशत से उसका दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है . मायावती इस खतरे को भाँपते हुए अब जनता का गठबंधन और बूथ स्तर पर संवाद जैसी रणनीतियाँ अपना रही हैं . ग्राम चुपाल, सामाजिक संतुलन वाले प्रत्याशी और स्थानीय समीकरणों पर ज़ोर—ये 2027 की उनकी तैयारी के संकेत हैं .

कर्पूरी बनाम राहुल ! कांग्रेस-जदयू आमने सामने

'जननायक' के नाम पर सियासी खेल शुरू

पटना. बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी को जननायक कहने के बाद जदयू ने कड़ा एतराज जताया है. जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि जननायक का टाइटल कोई चुराकर नहीं ले सकता. यह उपाधि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ही दी जा सकती है. संजय झा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी कोशिश कर लें, जनता उन्हें कभी जननायक स्वीकार नहीं करेगी.

जदयू की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया. पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बयान दिया कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठाने वाले सच्चे जननायक हैं. उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कांग्रेस ने हमेशा किया है और कांग्रेस ही उन्हें सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का प्रतीक मानती रही है. प्रेमचंद मिश्रा ने बीजेपी और जदयू पर हमला करते हुए कहा कि वही लोग कर्पूरी ठाकुर को पद से हटाने के असली जिम्मेदार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तब जदयू और बीजेपी के नेताओं ने सदन में वोट कर उन्हें सत्ता से हटाया था. ऐसे में आज वे लोग उनकी विरासत की बात करके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं.

सियासी संदेश और चुनावी एंगल- विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को जननायक बताना और उसके बाद जदयू का विरोध दरअसल आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति से जुड़ा है. कांग्रेस इस मुद्दे की छवि को जनता के नेता के रूप में स्थापित करना चाहती है. दूसरी ओर जदयू इस मुद्दे को अपनी जातीय और सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़कर भुनाना चाहती है.

> **बिहार में नया विवाद खड़ा**
> जननायक की सियासत ने बिहार में नया विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस राहुल गांधी को जनता का असली नेता साबित करने में जुटी है, जबकि जदयू इस उपाधि को सिर्फ कर्पूरी ठाकुर तक सीमित रखना चाहती है. आने वाले चुनावों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक हथियार बनता है, यह देखना दिलचस्प होगा.

क्या फिर बीजेपी में शामिल होंगे पवन सिंह?

आरा. दिल्ली से भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बीच मुलाकात की कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं. एक तस्वीर खुद सिने स्टार पवन सिंह ने अपने इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट किया है.

अपने पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा है एक नई सोच के साथ नई मुलाकात. इसे लेकर राजनीति गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. बिहार और शाहाबाद यानी भोजपुर, बक्सर, कैमुर और रोहतास जिला की राजनीति के लिहाज से ये तस्वीर काफी खास मानी जा रही है. एक तस्वीर में पवन सिंह

सोफ़ा पर बैठकर साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. दूसरी तस्वीर छत पर बातचीत करते देखा जा रहा है. इसके अलावा एक और तस्वीर में दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं.गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव के समय दोनों के बीच खटास को लेकर इंटरनेट मीडिया पर बातें सामने आई थीं. सिने स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ें थे.

विशेष भाजपा की एक खोज खत्म होते ही शुरू हुई दूसरी तलाश

कौन लेगा राधाकृष्णन की जगह?

मुंबई. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने गत रविवार शाम को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया. अब सबकी निगाहें विपक्ष की ओर टिकी हुई हैं.

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' भी इस चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था. जिसके बाद नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए मंथन जारी था, जो सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने के बाद पूरा हुआ. लेकिन भाजपा की एक तलाश खत्म होते ही दूसरी खोज शुरू हो गई है. सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है. 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने से पहले उन्हें राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना होगा. इससे महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा. ऐसे में भाजपा और एनडीए गठबंधन में अब राज्यपाल के लिए नए चेहरे की तलाश करनी होगी.

वैसे पूरे देश में संघ की अच्छी पकड़ है, लेकिन महाराष्ट्र संघ के लिए खास है. क्योंकि इसका मुख्यालय नागपुर में है. ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए भाजपा ऐसे को ऐसे चेहरे की तलाश होगी जो साफ-सुथरी छवि वाला हो और संघ में अच्छी पैठ रखता हो, ताकि राज्य सरकार के साथ-साथ भाजपा और संघ में तालमेल बना रहे.

चुनावी-राजनैतिक और जातिगत समीकरणों पर नजर- वहीं भाजपा का ध्यान चुनावी, राजनैतिक और जातिगत समीकरणों पर रहेगा. महाराष्ट्र में इसी साल निकाय चुनाव होने हैं. वहीं कुछ राज्यों में अलगे कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में किसी भी नाम को सामने लाने से पहले जातिगत, राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी. जिससे न केवल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव बल्कि अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा हो सके.

> **राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश भी जारी**
> भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में भी जुटी हुई है . जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नए अध्यक्ष के बनने तक वे इस पद पर बने रहेंगे . नए अध्यक्ष को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मंथन जारी है . ऐसे में देखना अहम होगा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए कौन सा चेहरा सामने लाती है .